

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग:

देहरादून : दिनांक 16 अक्टूबर, 2007

विषय: जनपद देहरादून के अन्तर्गत लक्ष्मण चौक, विधान सभा क्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 636/V-श.वि.-06-476(सा.)/04-टी0सी0, दिनांक 25.3.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के माध्यम से स्वीकृत रु. 184.41 लाख के सापेक्ष मात्र रु. 84.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्काल में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र सं0-1315/200, दिनांक 28.05.2007 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर उपरोक्त स्वीकृत कार्य की अवशेष रु. 99.68 लाख (रु. निम्नानुबन्ध लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0 478/V-2007-476(सा.)/04- टी0सी0, दिनांक 28.3.2007 द्वारा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी का पी.एल.ए. न होने के कारण उक्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-सी.एन.-37/ श0वि0/आ0-05-371 (सा0)/04, दिनांक 31 मार्च, 05 के माध्यम से नगर निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रु0-5.00 करोड़ में से आहरित करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. उक्त धनराशि को आपके द्वारा स्वीकृति का आदेश मुख्य नगर अधिकारी को शासनादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करके नगर निगम के पी.एल.ए. में रखी धनराशि से उक्त आदेश की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी और इसकी सूचना निदेशक शहरी विकास निदेशालय एवं मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम देहरादून को साथ ही साथ उपलब्ध करा दी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु Third Party Quality Checking की व्यवस्था की जायेगी जिस हेतु संबंधित संस्थाओं से अनुबन्ध होने के उपरान्त आवश्यक निदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
7. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तापुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रुल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
8. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

कमरा

9. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त प्रयोग के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
10. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
11. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अग्रोत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
12. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, को स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
13. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
14. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
15. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर उपयोग दिनांक 31.3.08 तक करके प्रस्तर-13 का विवरण भी उक्त तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-472/XXVII(2)/2007 दिनांक-08 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय


( शत्रुघ्न सिंह )  
सचिव।

संख्या 91 (1)/IV/2007, तददिनांक। 16/10/07

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकल्प, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
8. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मायावती ठाकुरियाल)  
अनु सचिव।